सवाल पूछना चाहता हूं कि उधर की जनता और उधर के जनप्रतिनिधि चार दिन किधर से दिल्ली आयेंगे, वे इसकी भी व्यवस्था बतायें कि ये किधर से आयेंगे जैसा कि हमारे सदस्य ने बताया कि आजमगढ़ में जनप्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा है और आजमगढ़ जनपद एक कमिश्निरी है इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इसको प्रमुख नगरों से जैसे कलकत्ता से, मुम्बई से, मद्रास से संबद्ध करने की क्या कोई योजना बनाई है? अगर योजना बनाई है तो वह कितने दिन में क्रियान्वित होगी और अगर नहीं बनाई है तो क्यों नहीं बनाई है?

श्री राम विलास पासवान: उपसभापति जी, मैंने कहा कि मऊ-शाहगंज के रास्ते से सिर्फ एक गाड़ी चल रही है। लेकिन उसके अलग-बगल में गोरखपुर है, वाराणसी है वहां से जो लिंक लाइन है उससे 9 गाड़ियां दिल्ली के लिए चल रही है। जहां तक उनका दूसरा सवाल है, उसके संबंध में मैंने पहले ही जवाब दे दिया है।

देश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

*144. **डा० महेश चन्द्र शर्मा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम देश में राज्य-वार कौन-कौन से जिलों में चल रहा है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने यह कार्यक्रम भारत को दिया है या सरकार ने इसे विश्व बैंक से मांगा है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) इस संदर्भ में विश्व बैंक कितनी राशि खर्च करने वाला है और क्या उक्त राशि अनुदान के रूप में होगी अथवा ऋण के रूप में होगी;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम के लिये कोई शर्त लगायी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को मूर्त रूप देने संबंधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992 में यथा संशोधित) के लक्ष्य को ध्यान में रखकर 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया। कार्यक्रम के लिए विदेशी वित्त पोषण विकासशील देशों में सभी के लिए शिक्षा परियोजनाओं की मदद करने संबंधी जोमतियन सम्मेलन में अंतराष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गई प्रतिबद्धता तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) द्वारा यह सहायता प्राप्त करने के संबंध में निर्धारित किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप है।

विश्व बैंक डी०पी०ई०पी० चरण-I के लिए 260.3 मिलीयन अमरीकी डालर की सहायता दे रहा है जिसके अंतर्गत 7 वर्ष की अवधि में असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के 23 जिले शामिल होंगे तथा डी०पी०ई०पी० II के तहत 11 राज्यों नामतः असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 70 जिलों के लिए 450.8 मिलीयन अमरीकी डालर (सह वित्त पोषण व्यवस्था के तहत 425 मिलीयन अमरीकी डालर की आई०डी०ए० क्रेडिट तथा 25.8 मिलीयन अमरीकी डालर का नीदरलैंड सरकार से अनुदान) की राशि सहायता के रूप में दे रहा है। जिन जिलों को विश्व बैंक की सहायता प्राप्त हो रही है उनके नाम विवरण I में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता मानक शर्तों और विनियमों पर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई०डी०ए०) से आसान ऋण के रूप में है। क्रेडिट समझौता के तहत, कार्यक्रम के चरण I और II में संबंधित राज्य सरकारों को प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय को वास्तविक रूप से क्रमशः 1991-92 तथा 1995-96 के स्तरों पर रखना होगा।

विवरण-I

राज्यों/जिलों की सूची

क्र०सं०	राज्य का नाम	शामिल किए गए जिले	
		डी०पी०ई०पी०-I	डी०पी०ई०पी०-II
1.	असम	धुब्री, दारंग, कार्बी आंगलांग, मोरीगांव	बरपेटा, बोगाईगांव, गोलपाड़ा कोकड़ाझाड़, सोनितपुर
2.	हरियाणा	कैथल, जींद, हिसार, सिरसा	भिवानी, गुड़गांव, मोहिंदरगढ़
3.	कर्नाटक	रायचूर, मंड्या, कोलार, बेलगाम	बंगलौर देहात, गुलबर्गा, मैसूर, बिदर, बेल्लारी, बिजापुर, धारवाड़
4.	केरल	कसारगोड़े, व्यानाड, मल्लापुरम	इडुक्की, पालक्काड, तिरूवनंतपुरम
5.	तमिलनाडु	धरमपुरी, तिरूव-अन्नामलाई, संबुवरयार, दक्षिण आरकोट	पैरम्बदूर, रामनाथपुरम, पुडुकोट्टइ
6.	महाराष्ट्र	परभनी, नांदेड, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, लातूर	बीड, धूले, गढ़चिरौली. जालना
7.	मध्य प्रदेश		भींड, मुरैना, सियोनी, मंडला, शिवपुरी, झबुआ, बस्तर, शाहजहांपुर, खारगोना, दतिया, देवास विदिशा, दामोह, रायपुर, खांडवा
8.	उड़ीसा		संबलपुर, बैरागढ़, क्योंझर, बोलनगीर. धेनकनाल, गजपति, कालाहांडी, रायगढ़
9.	उत्तर प्रदेश		महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बदायूं, खीरी, ललितपुर, पिलीभीत, बस्ती, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सोनभद्र, देवरिया, हरदोई, बरेली, फिरोजाबाद
10.	हिमाचल प्रदेश		सिरमौर, लाहुल-स्पीति, चम्बा, कुल्लू
11.	गुजरात		बनासकंठा, पंचमहल, और डंगस

डा० महेश चन्द्र शर्मा: उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे देश को विदेशों में से कहीं से भी ऋण मिले तो हमारी सरकारें तुरन्तु लेने पहुंच जाती हैं। ये जो शिक्षा को सुदूर तक पहुंचाने के लिए विश्व बैंक से ऋण आ रहा है, यह लगभग एक अरब 16 करोड़ 20 लाख अमेरिकन डालर है। महोदया, मैं यह जानना चाहूंगा कि तीन साल हो गए इस प्रकल्प को लागू हुए क्या तीन साल में इसकी कोई समीक्षा हुई है और जो इसका समीक्षा तंत्र है उसके बारे में क्या मंत्री महोदय सदन में कुछ बतायेंगे?

SHRI S.R. BOMMAI: Madam, World Bank assistance is to the tun of Rs. 2300 crores, to be precise. I have given the names of districts and states which have been benefited. There is a monitoring agency which evaluates it at the state level and the district levei. The namber of additional schools that are opened and the number of additional teachers that are appointed, all these things are monitored every year.

डा० महेश चन्द्र शर्मा: मैडम, मैंने कहा है कि क्या यह समीक्षा प्रतिवेदन को सदन में रखेंगे? क्योंकि तीन साल हो गए इसकी अभी तक समीक्षा नहीं आई है। दूसरे रूप में, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो राशि वापस की जाएगी तो क्या इसको केवल सरकार वापस

करेगी या राज्य सरकारें भी मिलकर वापस करेंगी और इसका ब्याज कितना होगा?

SHRI S.R. BOMMAI: Madam, it will be paid by the Central Government only. The government of India has to pay the World Bank loan. The service charge is at the rate of three-fourth of one per cent per annum on the principal amount of credit withdrawn and outstanding and the committed charge on the amount not withdrawn is at a rate not exceeding half on one per cent per annum. The repayment period is 35 years which can be extended by ten years. That means, you have to pay it within 45 years with minimum of interest and this will be paid entirely by the Government of India.

डा० महेश चन्द्र शर्मा: ब्याज कितना है? ब्याज की दर क्या है?

SHRI S. R. BOMMAI: Half a per cent.

डा० महेश चन्द्र शर्मा: समीक्षा की रिपोर्ट...

उपसभापति: 12 बज गए हैं। Quesitor Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

वडोदरा डिवीजन में आमान परिवर्तन

*145. **श्री गोपालसिंह जी सोलंकी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम रेलवे के अंतर्गत वडोदरा डिवीजन की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु आमान परिवर्तन कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या वडोदरा विभागीय प्रबंधक ने कोई विस्तृत प्रारूप प्रस्तुत किया है;

(ङ) क्या [illegible] आमान परिवर्तन कार्यक्रम हेतु [illegible] की गयी है;

[illegible] तो उसके [illegible] हैं; और

(छ) कितनी मीटर गेज लाइन को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बदला नहीं गया है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में एक छोटी साल्ट साइडिंग धांगधा-कुडा (22 कि०मी०) और कुछ छोटी लाइनों के अलावा कोई मीटर लाइन नहीं है। मीटर लाइन की इस साल्ट साइडिंग के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है और इस कार्य को 1997-98 के पूरक बजट में शामिल कर लिया गया है। भरुच-सामनी-जम्बूसर-विश्वामित्री (95.54 कि०मी०), सामनी-दाहेज (40 कि०मी०), जम्बूसर-कावी (26 कि०मी०) भादरण-बोचासण-पेटलाद-नडियाद (59 कि०मी०), रानू पिपरी-भादरण (26 कि०मी०) तथा मियागाम-करजन डभोई-साबलिया (80 कि०मी०) छोटी लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कर लिए गए हैं और ये विरार और अहमदाबाद के बीच तीसरी लाइन परियोजना, जो इस मंत्रालय के विचाराधीन है, के सर्वेक्षण का एक भाग हैं।

(घ) इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक/वडोदरा द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ङ) और (च) अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इनमें से किसी भी लाइन पर कार्य शुरू होने पर इस मंडल की मौजूदा मीटर लाइनों/छोटी लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए धनराशि निर्धारित की जाएगी।

(छ) 22 कि०मी० लम्बी धांगधा-कुडा साल्ट साइडिंग के आमान परिवर्तन का कार्य 1997-98 के पूरक बजट में शामिल कर लिया गया है।

Forest Policy

*146. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the current forest policy in order to ensure more involvement of local communities in guarding and managing forests;

(b) if so, the details thereof; and

(c) Government's stand on World Forest Treaty?